

जिला पंचायत के अंतर्गत प्रचलित योजनाएं

1. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना :-

इस योजनांतर्गत जिले में कुल 280220 पंजीकृत परिवारों को जाबकार्ड वितरित किए जाकर 01.04.07 से 31.03.08 तक 184497 मजदूरों को रोजगार की मांग करने पर रोजगार उपलब्ध कराया गया। ग्रामीण परिवारों को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। रोजगार उपलब्ध न होने की दशा में बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का प्रावधान है। इस प्रकार योजना प्रारंभ से 31.03.2008 तक राशि रु. 247 करोड़ रुपये व्यय कर 237 लाख मानव दिवस अर्जित किये गये, तथा 6247 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं एवं 10417 कार्य प्रगतिरत हैं।

उपयोजनायें :-

(1) कपिलधारा :- योजनांतर्गत जिले में वित्तीय वर्ष 2007-08 में 1407 कूप पूर्ण किये जा चुके हैं जिस पर 1758.75 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

(2) नंदन फलोद्यान :- वित्तीय वर्ष 2007-08 में आम, आंवला, नीबू, अमरूद की प्रजातियों के कुल 969.04 हैक्टेयर में 49672 फलदार पौधों का रोपण किया गया। जिस पर कुल व्यय 231.17 लाख रुपये हुआ।

(3) भूमि शिल्प :- योजनांतर्गत जिले में वित्तीय वर्ष 2007-08 में 14135 हितग्राहियों के खेतों में 994758.75 मी. मेढ़ बंधान का कार्य पूर्ण किया जा चुका है जिस पर 60.93 लाख रुपये व्यय हुए हैं।

(4) शैलपर्ण उपयोजना :- योजनांतर्गत जिले में वित्तीय वर्ष 2007-08 में 12608 मी.कंटूर ट्रेन्च, 131 गली प्लग एवं 32 हैक्टेयर चारा विकास का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। जिसमें कंटूर ट्रेन्च में 140.09 लाख, गली/बोल्डर चैक में 51.614 लाख तथा चारा विकास में 15.71 लाख रुपये व्यय किये गये हैं।

2. समग्र स्वच्छता अभियान :-

योजनांतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता हेतु शौचालय, नाडेप, कचराघर आदि का निर्माण किया जाता है । गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को शासन द्वारा 1200/- रुपये एवं हितग्राही अंशदान 300.00 रुपये (कुल 1500.00 रुपये) प्रति शौचालय निर्माण हेतु प्रदाय किये जाते हैं । संपूर्ण ग्राम पंचायत में शौचालय निर्माण होने पर माननीय राष्ट्रपति महो.द्वारा "निर्मल ग्राम पंचायत" का पुरस्कार प्रदान किया जाता है । वर्ष 2006-07 में जिले की 24 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया गया था । वर्ष 2007-08 हेतु जिले की 109 ग्राम पंचायतें निर्मल ग्राम पंचायत हेतु प्रस्तावित हैं । वर्ष 2008-09 हेतु 329 ग्राम पंचायतें निर्मल ग्राम पंचायत पुरस्कार हेतु प्रस्तावित हैं ।





3. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना :-

इस योजनांतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 10 सदस्यों के समूह को आर्थिक सुदृढीकरण हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण एवं अनुदान दिया जाता है । जिले में योजना प्रारंभ से वित्तीय वर्ष 07-08 तक कुल 5585 स्व सहायता समूहों का गठन किया गया है । गठित समूहों में बी.पी.एल.परिवार के 63209 सदस्यों को जोड़ा गया है । कुल गठित समूहों की कुल बचत राशि 545.25 लाख है । वर्ष 07-08 में जिले के वित्तीय लक्ष्य 704.16 लाख के विरुद्ध उपलब्धि 820.18 लाख रही ।

4. बी.आर.जी.एफ. :-

बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड (पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष) का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अधो संरचना सुविधाओं को विकसित करना तथा प्रशिक्षण व क्षमता विकास है । अधोसंरचना सुविधाओं में आंगनबाड़ी भवन, पशु औषधालय, पंचायत भवन, आयुर्वेदिक औषधालय, उप स्वास्थ्य केन्द्र शवदाह गृह, सामुदायिक भवन, नल जल योजना, अपना घर, टेलीफोन बिल भुगतान आदि आते हैं ।

इस योजनांतर्गत जिले में 447 अपना घर स्वीकृत हैं जिसमें से 215 को राशि जारी की जा चुकी है । 446 टेलीफोन स्थापित किये जा चुके हैं । 873 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है । जिले में जनपदवार 2 ब्लाक रिसोर्स सेंटर पूर्ण हो चुके हैं, शेष 6 प्रगतिरत हैं । शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अधो संरचना सुविधाओं के कार्य प्रगति पर हैं ।

5. मध्याह्न भोजन योजना :-

जिले की 2197 प्राथ.शाला के 17786 तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकासखंड की 91 शालाओं की 1127 छात्र-छात्रायें इस योजना से लाभान्वित हुए । शासन के नये निर्देशानुसार जिले के 619 स्वयं सहायता समूह द्वारा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है ।

6. इंदिरा आवास योजना :-

इस योजनांतर्गत वर्ष 2007-08 हेतु 733 नवीन आवास एवं 204 उन्नयन आवास का लक्ष्य प्राप्त हुआ था । वित्तीय वर्ष के अंत तक 647 नवीन आवास एवं 173 उन्नयन आवास पूर्ण कराये जा चुके थे । नवीन आवास हेतु 25000 तथा उन्नयन आवास हेतु 12500 प्रति आवास के मान से कुल राशि 203.72 लाख ग्राम पंचायतों को दी गई ।

वित्तीय वर्ष 2008-09 नवीन आवास का लक्ष्य 733 तथा उन्नयन आवास का लक्ष्य 190 प्राप्त हुआ है । शासन द्वारा इस वित्तीय वर्ष में नवीन आवास हेतु 35000 रुपये एवं उन्नयन आवास हेतु 15000 रुपये प्रति आवास के मान से निर्माण राशि निश्चित की गई है । जिले को प्राप्त राशि 47.528 लाख प्राप्त हुई है ।

7. मुख्यमंत्री आवास/अपना घर योजना :-

इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आवासहीन परिवारों को नवीन आवास, स्वच्छ शौचालय एवं धुआं रहित चूल्हा सहित निर्माण हेतु 25000 रुपये के मान से राशि दी जाकर 23 नवीन आवासों का कार्य जारी है ।

8. मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना :- योजनांतर्गत समस्त 18 से 60 वर्ष के भूमिहीन, खेतीहर मजदूरों को पंजीकृत किया जाकर उन्हें फोटोयुक्त परिचय पत्र प्रदान किया जाता है तथा उन्हें प्रसूति सहायता, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता एवं मृत्यु पर अंत्येष्टि सहायता, छात्रवृत्ति सहायता प्रदान

की जाती है । जिले में अभी तक 25272 व्यक्तियों को परिचय पत्र का वितरण किया गया है ।

9. राजीव गांधी जलग्रहण मिशन :-

ग्रामीण क्षेत्रों की पड़त भूमि बहुल्यता वाले क्षेत्रों में मिट्टी एवं पानी का कटाव रोकने एवं भूजल वृद्धि हेतु ग्रामवासियों के सहयोग से भूजल संवर्धन के कार्य किये जाते हैं । इस योजनांतर्गत 257 ग्रामों के 87825 हैक्टेयर क्षेत्र में भू एवं जल संवर्धन के कार्य में राशि 1032.775 लाख रूपये व्यय किया गया है ।